RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 238
दि. 29.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं: धार्मिक उन्माद और जातीय विद्वेष पर योगी सरकार का सख्त संदेश

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने, जातीय विद्वेष भड़काने और समाज की शांति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। 'पुलिस मंथन' वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिए कि अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी सख्ती से लागू की जाए और कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई न हो।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और इस प्रगति को बाधित करने की कोशिश करने वाले तत्वों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाना सरकार और पुलिस की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था केवल पुलिस का विषय नहीं, बल्कि यह समाज में विश्वास, शांति और सुरक्षित वातावरण का आधार है। अगर कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने या जाति के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, तो उनके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर अराजकता को बढ़ावा न मिले।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट, सुनियोजित दुष्प्रचार, डीपफेक वीडियो, डार्कवेब और साइबर अपराध अब कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माध्यमों के जरिए अफवाहें फैलाई जाती हैं, समाज में अविश्वास पैदा किया जाता है और धार्मिक व जातीय तनाव को हवा दी जाती है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाए और सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट, वीडियो या संदेश पर तत्काल संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्व महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग कर नए-नए संगठन बनाते हैं और उनके माध्यम से समाज में भ्रम, तनाव और अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संगठनों के पीछे की मंशा को समझना और उनके पूरे नेटवर्क को उजागर करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस इन संगठनों की पृष्ठभूमि की गहन जांच करे, उनके वित्तीय स्रोतों, संपर्कों और गतिविधियों का पता लगाए और कानून के तहत सख्त कार्रवाई कर पूरे तंत्र को ध्वस्त करे।

धार्मिक कन्वर्जन के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नेटवर्क सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस तंत्र को चाहिए कि वह ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे और किसी भी संदिग्ध प्रयास को शुरुआती स्तर पर ही विफल कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक का बेहतर उपयोग कर इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया जाए, ताकि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़ी सीमाओं के कारण उत्तर प्रदेश की सुरक्षा चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। आतंकी गतिविधियों, अवैध तस्करी और संगठित अपराध के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत करना होगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम और वित्तीय ट्रेल जैसे साधनों के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित अवैध गतिविधियों और धर्मांतरण रैकेट पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अब तक की पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच रियल-टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाए, ताकि अपराधी नेटवर्क को समय रहते तोड़ा जा सके और उनका मनोबल पूरी तरह खत्म किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं और समाज के भविष्य से भी जुड़ा हुआ गंभीर विषय है।

गो-तस्करी के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केवल निचले स्तर के अपराधियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। पुलिस को चाहिए कि वह पूरे नेटवर्क की पहचान करे और गो-तस्करी के मास्टरमाइंड तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक इस तरह के संगठित अपराध के पीछे बैठे मुख्य लोगों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस दिशा में पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने इसे और तेज करने के निर्देश दिए।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो लोग धार्मिक उन्माद, जातीय विद्वेष या अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और दृढ़ कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है।

सीतापुर में प्रेम विवाह करने वाले नवविवाहित दंपति का रहस्यमयी निधन, मंदिर परिसर में पेड़ से लटके मिले शव

(जीएनएस)। सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक दिल दहला देने वाला और रहस्यमयी मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। लहरपुर थाना क्षेत्र के अनियापुर गांव स्थित मंदिर परिसर में खुशीराम (22) और मोहिनी (20) के शव रविवार को एक पुराने पेड़ से लटके पाए गए। यह आश्चर्य की बात है कि दोनों ने इसी मंदिर में केवल 21 दिन पहले प्रेम विवाह किया था। इस घटना ने न केवल उनके परिवार और गांव वालों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि पूरे जिले में इसे लेकर चर्चा और शोक का माहौल बन गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से मामले में रहस्य और बढ़ गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों शवों के पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि हत्या के सभी पहलुओं

को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और जांच की जा रही है कि कहीं यह कोई संगठित साजिश तो नहीं थी।

गांव में लोगों का कहना है कि दोनों के परिवार शुरू में विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों को स्वीकार कर आशीर्वाद भी दिया। इसके बावजूद मंदिर परिसर में इस प्रकार दोनों के शव मिलने से पूरे इलाके में सवाल खड़े हो गए हैं। हर किसी के मन में यही संदेह है कि यह आत्महत्या थी या किसी ने किसी साजिश के तहत उनकी जान ले ली। इस तरह की घटनाएं समाज में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की सच्चाई सामने आएगी। अधिकारियों का कहना है कि वे सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का निष्पक्ष और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और जांच की निगरानी कर रहे हैं।

इस रहस्यमयी मौत ने इलाके में शोक और भय दोनों का माहौल बना दिया है। गांव वाले और परिजन दोनों के अचानक और अप्रत्याशित निधन से गहरे सदमे में हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। ग्रामीणों और परिवार वालों की चिंता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है।

यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है कि प्रेम विवाह, पारिवारिक असहमति, सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतना अत्यंत आवश्यक है। आशंका जताई जा रही है कि अगर इस प्रकार के मामलों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अदालत के आदेशों की अनदेखी पर सख्त संदेश अवमानना के लिए सर्वोच्च अधिकारी ही होंगे जिम्मेदार

(जीएनएस)। इलाहाबाद। प्रशासनिक तंत्र में जिम्मेदारियों के बंटवारे या विभागीय भ्रम को अदालत के आदेशों के अनुपालन से बचने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी अदालती आदेश का पालन नहीं होता है तो संबंधित सरकारी विभाग का सर्वोच्च अधिकारी ही अवमानना की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले में अदालत ने यह कहते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराया कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि उसके प्रशासनिक ढांचे के भीतर किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और न्यायालय के आदेशों का पूर्ण, समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन कराना प्रदेश सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है और यदि विभिन्न विभागों या अधिकारियों के बीच काम के बंटवारे को आधार बनाकर आदेशों की अनदेखी

की जाती है, तो इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासनिक तंत्र में यह तय करना सरकार का आंतरिक विषय है कि किस विभाग या अधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन इसका खामियाजा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में देरी या असफलता के रूप में जनता को नहीं भुगतना चाहिए। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी और वह जवाबदेही सर्वोच्च अधिकारी पर ही आएगी। यह टिप्पणी उस अवमानना मामले में की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता विनय कुमार सिंह की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1977 में किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 1982 और 1984 में मुआवजा तय करने के आदेश तो पारित हुए, लेकिन वास्तविक रूप से मुआवजे की राशि उन्हें कभी नहीं दी गई। इसके बावजूद, उनकी जमीन पर उनका कब्जा बना रहा। बाद में वर्ष 2013 में लागू हुए नए भूमि अधिग्रहण कानून के बाद मुआवजे की राशि सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया और दलील दी कि अधिग्रहण की कार्यवाही अपनी वैध अवधि पूरी कर चुकी थी।

याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में उच्चतम न्यायालय के पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिश्रीलाल सोलंकी मामले का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि समय सीमा के भीतर न तो उचित मुआवजा दिया गया और न ही भूमि पर वास्तविक कब्जा लिया गया, इसलिए अधिग्रहण स्वतः समाप्त माना जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने अपनी भूमि को अपने पक्ष में मुक्त किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद यह माना कि चूंकि मुआवजे की राशि न तो समय पर दी गई और न ही वह विधि सम्मत थी, इसलिए भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही कानून के तहत समाप्त हो चुकी है। अदालत ने स्पष्ट आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता की भूमि उन्हें वापस की जाए। इसके बावजूद जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। पहली अवमानना याचिका में अदालत ने अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के लिए समय दिया, लेकिन इसके बाद भी जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो याचिकाकर्ता ने दूसरी अवमानना याचिका दाखिल की। मामले के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शुरुआत में भूमि का अधिग्रहण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इस भूमि से जुड़ा मामला शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसी विभागीय बदलाव को आधार बनाकर आदेश के अनुपालन में लगातार देरी होती रही।

दिल्ली हाईवे पर धधकी कार, रात के अंधेरे में मची अफरातफरी, आगजनी या हादसा—हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

(जीएनएस)। बिजनौर। बिजनौर–दिल्ली हाईवे पर शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बैराज रोड स्थित हेमराज कॉलोनी के पास एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही पलों में कार से

उठती लपटों और धुएं ने पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा कर दिया। हाईवे पर गुजर रहे वाहन रुक गए और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार सवार लोगों की जान बाल-बाल बची।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में कुछ यात्री सवार थे, जो किसी कारणवश रास्ते में खराबी आने के बाद हाईवे पर ही रुक गए थे। इसी दौरान चालक और यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंचने का आरोप लगाया जा रहा है। चालक अबरार ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि यात्रियों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में कार में आग लगा दी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। जली हुई कार का ढांचा सड़क किनारे पड़ा रहा, जिससे देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। आसपास के लोगों का कहना है कि आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही लपटें दिखाई दे रही थीं और तेज धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई दीं।

शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार में आग तकनीकी खराबी के चलते स्वतः लगी या फिर किसी ने जानबूझकर आगजनी की है। पुलिस ने कार चालक की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आग लगने की असली वजह सामने आ सके।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मामला दुर्घटना का है या साजिश के तहत आगजनी की गई। फिलहाल इस सनसनीखेज घटना ने बिजनौर–दिल्ली हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था और रात के समय यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने जांच अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग करते हुए सीबीआई से संपर्क किया

(जीएनएस)। उन्नाव। वर्ष 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क कर तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। यह मामला उस समय का है जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप साबित हुआ और उन्हें दोषी ठहराया गया। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को सशर्त निलंबित करते हुए उसे जमानत दी, जिससे पीड़िता और उसके परिवार में चिंता और निराशा बढ़ गई। हालांकि, सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा भी काटनी है।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने दुर्भावना और कपटपूर्ण तरीके से मामले की जांच की, ताकि सेंगर और अन्य आरोपियों को लाभ मिल सके। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी ने आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेजों का उपयोग किया, जिसमें उन्हें एक सरकारी स्कूल की छात्रा के रूप में दिखाया गया और जन्मतिथि में भी हेरफेर की गई। जबकि वास्तविकता यह थी कि उसने कभी उस स्कूल में प्रवेश नहीं लिया था। इसके अलावा, आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि पीड़िता हीरा सिंह नाम की महिला का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उसने कभी उस फोन का इस्तेमाल नहीं किया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपपत्र में कई बयानों को पीड़िता के हवाले से गलत तरीके से शामिल किया गया, जिससे आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन किसी भी कार्रवाई का पालन नहीं किया गया।

2017 में बलात्कार के समय पीड़िता नाबालिग थी। निचली अदालत ने भी जांच अधिकारी के रवैये पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बयान दर्ज करने में पक्षपात दिखाई दिया। पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी ने सेंगर और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए जांच में जानबूझकर चूक की और तथ्य हेरफेर किए।

सीबीआई ने मुकदमे के दौरान यह दावा किया कि मोबाइल फोन पर किए गए जांच अधिकारी के दावे केवल राय थे और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधिकारी आरोपी का पक्ष ले रहा था। लेकिन अदालत ने टिप्पणी की थी कि जांच निष्पक्ष नहीं की गई और अधिकारी/सीबीआई का रवैया पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के बयान को अविश्वसनीय साबित करने का संकेत देता है।

अब पीड़िता की यह नई शिकायत सीबीआई के समक्ष एक नई जांच की मांग को लेकर महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है। इस कदम से न केवल जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठते हैं, बल्कि उन प्रक्रियाओं की भी समीक्षा आवश्यक हो जाती है जिनके तहत जांच की निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया जाता है।

डीजे बजाने पर निकाह रद्द, फोन पकड़े जाने पर जुर्माना: उत्तर भारत में खाप पंचायतों के विवादित फरमानों ने मचाई हलचल

(जीएनएस)। उत्तर भारत में खाप पंचायतें हमेशा से अपने सख्त और विवादित फैसलों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, और हाल के दिनों में मथुरा, बागपत, जालोर और मुजफ्फरनगर में उनके तुगलकी फरमानों ने एक बार फिर जनता और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। इन पंचायतों ने शादी, स्मार्टफोन, पहनावे और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों में नियम तय किए हैं, जिन्हें वह सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी मानती हैं। हालांकि, इन फैसलों ने समाज में बहस और विरोध की आग भी भड़का दी है। मथुरा की खाप पंचायत ने मुस्लिम शादियों पर नया नियम लागू किया है। पंचायत ने स्पष्ट किया कि अब किसी शादी में डीजे बजाने पर मौलाना निकाह नहीं पढ़ेंगे। साथ ही, मैरिज होम में निकाह कराने की अनुमति नहीं होगी और सलामी उपहार तथा आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत का कहना है कि यह फैसला शादी को सरल और पारंपरिक रूप में रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि समाज में फिजूलखर्ची और दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

बागपत की थंबा पट्टी मेहर देशखाप पंचायत ने भी अपने तुगलकी फरमान से सुर्खियां बटोरी हैं। पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है और हाफ पैंट पहनने पर रोक लगाई है, साथ ही पारंपरिक पहनावे अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा, पंचायत ने तय किया कि शादियां अब केवल घर या गांव में ही होंगी, मैरिज हॉल में नहीं। पंचायत का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को पारंपरिक मूल्यों के साथ जोड़ना बताया गया है।

जालोर की खाप पंचायत ने 'बहुओं' और कुंवारी लड़कियों के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। हालांकि भारी विरोध और कानून के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले पर पुनर्विचार की खबरें आई हैं। पंचायत ने यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया।

मुजफ्फरनगर के सोरम गांव की खाप पंचायत ने लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्त चेतावनी दी और इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने की मांग की। पंचायत ने युवाओं को सलाह दी कि वे अनावश्यक रील बनाने और सोशल मीडिया पर दिखावे के कंटेंट पर ध्यान देने के बजाय अपनी संस्कृति, धर्म और पारंपरिक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कंटेंट पर फोकस करें। इन फैसलों ने समाज में तीखी बहस को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाप पंचायतों के ये निर्णय सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानूनी अधिकार और आधुनिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से इनकी आलोचना भी होती है। समाज के विभिन्न वर्गों में इन फैसलों पर विरोध और समर्थन दोनों ही देखने को मिल रहे हैं।

कई परिवार और युवा इन निर्णयों को पारंपरिक समाज के दबाव के रूप में देख रहे हैं, जबकि पंचायतें इसे नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी मानती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसलों और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि युवा वर्ग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों सुरक्षित रहें।

उत्तर भारत की खाप पंचायतों के ये विवादित फरमान यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में परंपराओं और आधुनिकता के बीच जुझारूपन लगातार बना हुआ है। यह मामला केवल सामाजिक बहस का विषय नहीं, बल्कि प्रशासन और न्यायपालिका के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार और पंचायतों के तुगलकी फैसले अक्सर टकराते दिखाई देते हैं।

कृष्ण कुमार बिश्नोईः माफियाओं के खिलाफ निडर पुलिस अधिकारी, यूपी सरकार ने किया सम्मानित

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके माता-पिता भी साथ आए और अपने बेटे के इस सम्मान को देखकर गर्व से दुलार करते नजर आए। कृष्ण बिश्नोई की पहचान उत्तर प्रदेश पुलिस में एक साहसी और निडर आईपीएस अधिकारी के रूप में है, जो माफियाओं, अपराधियों और ठग गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण कुमार बिश्नोई राजस्थान के मूल निवासी हैं और 2018 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मेरठ में तैनाती के दौरान उन्होंने कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो की कोठी को बुलडोजर से ढहा दिया था। उस समय बदन सिंह पर पांच लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और कुख्यात अपराधी सुशील मूंछ को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके बाद गोरखपुर में एसपी सिटी रहते हुए बिश्नोई ने माफियाओं की 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कराई।

एसपी बिश्नोई की अगुआई में पुलिस ने 10 साल से सक्रिय बीमा ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया, जो मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा कर करोड़ों रुपये हड़पता था। संभल पुलिस ने उनके नेतृत्व में 17 मामलों में 68 लोगों को गिरफ्तार कर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का खुलासा किया। अब तक बिश्नोई 800 करोड़ रुपये से अधिक की माफियाओं की संपत्ति कुर्क करवा चुके हैं। हाल ही में संभल में हुई हिंसा के दौरान भी बिश्नोई निडर होकर पत्थरबाजों के बीच गए और उन्हें समझाया कि बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद न करें। उनके साहस, प्रशासनिक कौशल और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनके माता-पिता ने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मान प्राप्त कर उसे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बताया।

कुल मिलाकर, कृष्ण कुमार बिश्नोई की कहानी साहस, निष्ठा और निष्पक्षता की मिसाल है। उनके संघर्ष और प्रभावी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सिमुलतला पुल पर भीषण रेल हादसा, सीमेंट से लदी मालगाड़ी बेपटरी होकर नदी में समाई, हावड़ा–पटना–दिल्ली रूट ठप

(जीएनएस)। बिहार में हावड़ा–पटना–दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर शनिवार देर रात एक बड़ा और गंभीर रेल हादसा सामने आया, जिससे पूरे रेल नेटवर्क पर अफरा-तफरी मच गई। जमुई–जसीडीह रेलखंड पर सिमुलतला स्टेशन के समीप स्थित सिमुलतला पुल पर सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल से नीचे बड़ुआ नदी में जा गिरे, जबकि एक दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी पर ही एक-दूसरे से टकराकर बुरी तरह फंस गए। इस दुर्घटना के चलते रात करीब 11:30 बजे से अप और डाउन दोनों रेल लाइनों पर परिचालन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद रेल मार्ग पर सन्नाटा पसर गया और कई एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। करीब दो दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिनमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों यात्री घंटों तक इंतजार करते रहे। ठंड और देर रात के कारण यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। कई यात्रियों ने स्टेशन परिसर में ही रात गुजारने को मजबूर होने की बात कही।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह मालगाड़ी जसीडीह से झाझा की ओर अप लाइन पर जा रही थी। टेलवा बाजार हाल्ट के पास पुल संख्या 676 पर पहुंचते ही अचानक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और संतुलन बिगड़ते ही कई डिब्बे पुल से नीचे नदी में गिर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। मालगाड़ी का इंजन और कुछ डिब्बे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंजन करीब 400 मीटर आगे टेलवा बाजार हाल्ट के पास खड़ा मिला।

घटना की सूचना मिलते ही मालगाड़ी के चालक कमलेश कुमार और गार्ड मनीष कुमार पासवान ने सिमुलतला स्टेशन को तुरंत जानकारी दी। इसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार, आरपीएफ ओपी प्रभारी रवि कुमार और पीडब्ल्यूआई रंधीर कुमार देर रात ही घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी मौके पर तैनात कर दी गईं।

आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही बहाली कार्य के लिए तकनीकी टीम को तुरंत आसनसोल से रवाना कर दिया गया। मालगाड़ी में कुल 42 डिब्बे थे, जिनमें से 23 डिब्बे पटरी पर सुरक्षित बताए गए हैं। दोनों इंजन भी सुरक्षित हैं, लेकिन नदी में गिरे डिब्बों को निकालना और क्षतिग्रस्त ट्रैक को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रेलवे प्रशासन ने युद्धस्तर पर बहाली कार्य शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द रेल यातायात को सामान्य किया जा सके।

दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी आसनसोल से सीतामढ़ी की ओर सीमेंट लेकर जा रही थी। इस हादसे के चलते न सिर्फ रेल यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि माल ढुलाई व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। तकनीकी खराबी, ट्रैक की स्थिति और गति समेत सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह बड़ा हादसा कैसे हुआ।

फिलहाल, सिमुलतला पुल और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें। इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में पूर्वांचल, सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कक्षा आठ तक के स्कूल बंद

(जीएनएस)। पूर्वांचल के आसमान पर इन दिनों कोहरे का ऐसा घना आवरण छाया हुआ है कि सुबह से लेकर दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन तक मुश्किल हो जा रहे हैं। शीतलहर अपने चरम पर है और ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत आसपास के जिलों में हालात लगभग एक जैसे बने हुए हैं। बीते एक सप्ताह से लगातार ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। आवश्यक कार्यों को छोड़कर लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और दिनभर कंबल, स्वेटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं।

शनिवार की तरह रविवार को भी सुबह से ही कोहरा छाया रहा। दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आई। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में चहल-पहल कम रही और जो लोग बाहर निकले, वे अलाव के पास सिमटे नजर आए। चाय की दुकानों पर भी भट्ठी के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा रही, जहां गर्म चाय के साथ ठंड से राहत पाने की कोशिश की जा रही थी। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और प्रयागराज तथा प्रतापगढ़ का न्यूनतम तापमान पांच से सात डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे गलन और कंपकंपी और बढ़ गई है।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी साफ दिखाई देगा और शीतलहर और तेज हो सकती है। सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप अधिक रहने की संभावना जताई गई है, जिससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जौनपुर जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के निर्देश पर कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए दो दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि जनपद के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त तथा सीबीएसई, आईसीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए 29 और 30 दिसंबर 2025 को अवकाश रहेगा। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ठंड और कोहरे के कारण किसी प्रकार की परेशानी न हो।

हालांकि, इस दौरान शिक्षकों और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए अवकाश नहीं रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और विभागीय कार्यों के साथ-साथ अन्य शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूर्व की भांति करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

कुल मिलाकर, घना कोहरा और शीतलहर ने पूरे पूर्वांचल की रफ्तार को धीमा कर दिया है। जनजीवन ठिठुरता नजर आ रहा है और लोग बेसब्री से मौसम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल, मौसम का मिजाज देखते हुए आने वाले कुछ दिन भी ठंड और गलन भरे रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

कैफे में जन्मदिन पार्टी पर बवाल, कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस की सख्ती, बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा

(जीएनएस)। बरेली के प्रेमनगर क्षेत्र में एक निजी कैफे में आयोजित जन्मदिन पार्टी उस समय विवाद का केंद्र बन गई, जब कुछ लोगों ने बिना तथ्य जाने धार्मिक आरोप लगाते हुए वहां हंगामा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बजरंग दल के पदाधिकारी दीपक पाठक, ऋषभ ठाकुर सहित 15–20 नामजद और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है।

घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब प्रेमनगर स्थित एक हॉस्टल में रहने वाली निजी कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। छात्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर शहर के 'दि डेन कैफे एंड रेस्टो' में एक छोटा सा निजी आयोजन रखा था, जिसमें उसके कुल दस दोस्त शामिल थे। इन दोस्तों में छह युवतियां और चार युवक थे, जो आपस में परिचित और सहपाठी बताए गए हैं। यह पूरी तरह निजी कार्यक्रम था और कैफे में सामान्य माहौल में पार्टी चल रही थी।

बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी व्यक्ति ने यह जानकारी फैला दी कि पार्टी में शामिल चार युवकों में से दो मुस्लिम समुदाय से हैं। इस सूचना के बाद बिना किसी पुष्टि या जांच के बात को धार्मिक रंग दे दिया गया और हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दे दी गई। कुछ ही देर में बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता कैफे के बाहर पहुंच गए और उन्होंने 'लव जिहाद' जैसे आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि कार्यकर्ता केवल बाहर तक ही नहीं रुके, बल्कि कैफे के भीतर भी घुस गए और वहां मौजूद लोगों से बहस करने लगे, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

कैफे में मौजूद अन्य ग्राहक और स्टाफ इस अचानक हुए हंगामे से सहम गए। जन्मदिन मना रही छात्रा और उसके दोस्त भी इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से परेशान हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने सभी को शांत कराया और संबंधित युवती तथा उसके साथ मौजूद लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ की। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल थी। किसी तरह का दबाव, बहकावा या अवैध गतिविधि सामने नहीं आई।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कैफे में कोई आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी और पूरा मामला केवल अफवाह और गलतफहमी के आधार पर तूल पकड़ गया। इसके बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में बजरंग दल के पदाधिकारी दीपक पाठक, ऋषभ ठाकुर समेत 15–20 नामजद और अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने कहा कि किसी भी संगठन को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि किसी को किसी गतिविधि पर आपत्ति है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए, न कि खुद हंगामा कर माहौल बिगाड़ा जाए। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। एक ओर लोग पुलिस की कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी चिंता जताई जा रही है कि निजी कार्यक्रमों में बिना ठोस आधार के धार्मिक आरोप लगाकर हंगामा करना समाज में तनाव बढ़ा सकता है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे पर ध्यान देने के बजाय लोग कानून पर भरोसा रखें। प्रेमनगर की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि निजी जीवन और सामाजिक स्वतंत्रता में दखल कहां तक उचित है। पुलिस प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्ती बरती जाएगी, ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे और किसी की व्यक्तिगत आजादी को नुकसान न पहुंचे।

रामकथा के समापन से पहले कानपुर में कवि कुमार विश्वास का आत्मीय स्वागत, सियासत और साहित्य का दिखा संगम

(जीएनएस)। कानपुर में रविवार को साहित्य, श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब सुप्रसिद्ध कवि और वक्ता कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सांसद रमेश अवस्थी के आवास पहुंचे। शहर में चल रही तीन दिवसीय रामकथा "अपने-अपने राम" के अंतिम दिन से पहले उनके आगमन को लेकर खास उत्साह देखा गया। लाल बंगला स्थित विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आवास पर उनके पहुंचने से पहले ही माहौल उत्सुकता से भरा हुआ था। जैसे ही कुमार विश्वास वहां पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरे परिवार के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। घर के वातावरण में औपचारिकता के साथ-साथ अपनापन भी साफ नजर आया, जहां कवि कुमार विश्वास ने महाना के परिजनों से भेंट कर हालचाल जाना और कुछ समय तक सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई।

इसके बाद कुमार विश्वास तिलक नगर स्थित सांसद रमेश अवस्थी के आवास के लिए रवाना हुए। उनके आगमन की सूचना पहले से मिलने के कारण वहां समर्थकों और शुभचिंतकों की मौजूदगी रही। जैसे ही वह सांसद के आवास पहुंचे, समर्थकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। सांसद रमेश अवस्थी के पुत्रों ने भी आगे बढ़कर कुमार विश्वास का अभिनंदन किया। आवास पर कुछ देर तक अनौपचारिक चर्चा का दौर चला, जिसमें साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े विषयों पर संवाद हुआ। यह मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं रही, बल्कि इसमें विचारों और संवेदनाओं का आदान-प्रदान भी देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि इन दिनों कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय रामकथा "अपने-अपने राम" का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुमार विश्वास राम के जीवन, उनके आदर्शों और मानवीय मूल्यों को समकालीन दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा के प्रति श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीते दो दिनों से हजारों की संख्या में लोग कथा स्थल पर पहुंचकर कवि कुमार विश्वास के मुख से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को सुन चुके हैं। उनकी ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण प्रस्तुति ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया है।

रामकथा के समापन दिवस पर श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के कथा का श्रवण कर सकें। विश्वविद्यालय परिसर में श्रद्धा, अनुशासन और उत्सव का वातावरण बना हुआ है। हर आयु वर्ग के लोग, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, बड़ी तन्मयता से कथा सुनते नजर आ रहे हैं। कुमार विश्वास का विधानसभा अध्यक्ष और सांसद के आवास पर पहुंचना शहर में चर्चा का विषय बना रहा। इसे साहित्य और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर रामकथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर ऐसे आत्मीय मुलाकातों से सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का भाव भी मजबूत हो रहा है। कुल मिलाकर, रामकथा के समापन से पहले का यह दिन कानपुर के लिए स्मरणीय बन गया, जहां राम की कथा, कविता की संवेदना और समाज के प्रमुख व्यक्तित्वों का मिलन एक साथ देखने को मिला।

बिहार के बाद यूपी में समाजवादी राजनीति के अंत की शुरुआत, 2027 में जनता देगी निर्णायक जवाब : ब्रजेश पाठक

(जीएनएस)। कानपुर में रविवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद हुए चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया और अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे ही यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी और वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, वैसे ही समाजवादी पार्टी का भी राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बेचैनी इसी बात से साफ झलकती है कि उन्हें आने वाले समय का अंदेशा हो चुका है और जनता अब उनके पुराने कारनामों को भूलने वाली नहीं है। निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जंगलराज बेहद करीब से देखा है। उस दौर में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि उसी उत्तर प्रदेश में आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज अपराधियों में कानून का भय है और गुंडे दुम दबाकर भाग रहे हैं। यह परिवर्तन भाजपा सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का परिणाम है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार-बार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2027 का चुनाव प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जनता एक बार फिर भाजपा को अपना समर्थन देगी। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब वहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ और उसके बाद चुनाव संपन्न हुए, तो वहां की जनता ने साफ संदेश दे दिया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी निष्पक्ष निर्णय होगा, वह समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाएगा।

संभल में मस्जिद के नाम पर आठ बीघा जमीन पर कब्जे के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार किसी भी तरह के अवैध कब्जे या कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी नाम या पहचान के तहत किया गया हो। कानून सबके लिए समान है और सरकार उसी सिद्धांत पर काम कर रही है।

कानपुर मेडिकल कॉलेज में जिंदा मरीज को मृत घोषित किए जाने के गंभीर मामले पर भी उपमुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस घटना से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और इससे आम लोगों का भरोसा भी प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो भी डॉक्टर या स्टाफ दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा।

लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की हुई बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी के भीतर संवाद और विचार-विमर्श की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से चलती रहती है और इसे किसी भी तरह से गलत अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, कानपुर दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पूरी तरह से राजनीतिक संदेश देने वाले रहे। उन्होंने साफ संकेत दिया कि भाजपा आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और समाजवादी पार्टी को जनता के बीच अपने पुराने शासनकाल का जवाब देना होगा। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश अब बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ खड़ी है। ऐसे में 2027 का चुनाव समाजवादी राजनीति के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा, जहां जनता अपने अनुभवों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

हर जिले में खतरनाक अपराधियों की सूची पुलिस का होगा हर गली तक दबदबा, 2026 के लिए हरियाणा पुलिस की सख्त अपराध रोधी रणनीति

(जीएनएस)। हरियाणा में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने वर्ष 2026 को निर्णायक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में डीजीपी ओ.पी. सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि अपराध की सोच, तैयारी और नेटवर्क को पहले ही चरण में तोड़ना पुलिस की प्राथमिकता होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि हरियाणा की आखिरी गली तक पुलिस का दबदबा दिखना चाहिए, अपराधियों का नहीं। इसी सोच के तहत राज्यभर में हिंसक अपराधियों, संगठित गिरोहों, ड्रग माफिया, साइबर अपराधियों और उभरते सुरक्षा खतरों पर पूर्व नियोजित और आक्रामक रणनीति लागू करने का खाका तैयार किया गया है। रणनीति के तहत स्पेशल टास्क फोर्स को राज्य के 100 सबसे खतरनाक और हिंसक अपराधियों की लाइव निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि प्रत्येक जिले को अपने-अपने क्षेत्र के 20 सबसे कुख्यात अपराधियों की अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सूचियों में हत्या, रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, संगठित गिरोहों से जुड़े आरोपी और सजायाफ्ता अपराधी शामिल होंगे। इन पर लगातार निगरानी, कानूनी पाबंदियां, मूवमेंट ट्रैकिंग और अवैध कमाई की आर्थिक जांच के जरिए दबाव बनाया जाएगा, ताकि अपराधी खुद को हर समय कानून के घेरे में महसूस करें। पुलिस नेतृत्व का मानना है कि जब अपराधी मानसिक रूप से घिरे रहेंगे, तभी अपराध की घटनाओं में स्थायी कमी आएगी।

शहरी क्षेत्रों में रंगदारी और संगठित अपराध, सीमावर्ती जिलों में ड्रग सप्लाई नेटवर्क और ग्रामीण इलाकों में जुआ, अवैध शराब और बदमाश तत्वों की सक्रियता वाले क्षेत्रों को क्राइम हॉटस्पॉट मानते हुए वहां पुलिस की निरंतर और प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। डीजीपी ने साफ किया कि पुलिस का उद्देश्य केवल रेड डालना नहीं, बल्कि अपराधियों की जड़ों तक पहुंचकर उनके संसाधन, नेटवर्क और संरक्षण को खत्म करना है। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ लड़ाई को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है, जहां 2026 में 'कमर्शियल क्वांटिटी' वाले मामलों पर विशेष फोकस रहेगा। ऐसे मामलों में सख्त जांच, मजबूत चार्जशीट और अदालतों में सजा की दर बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ड्रग माफिया की अवैध कमाई को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई को अनिवार्य हथियार के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया है, ताकि नशे के कारोबार की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सके।

बैठक में नशा मुक्ति व्यवस्था को सामाजिक न्याय विभाग से स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित किए जाने के हालिया फैसले को भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा गया। पुलिस अधिकारियों ने माना कि इससे डि-एडिक्शन सेंटरों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। जिलों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे केवल पकड़-धकड़ और जागरूकता तक सीमित न रहें, बल्कि युवाओं और बार-बार नशे की गिरफ्त में आने वाले लोगों को ठोस इलाज और पुनर्वास तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय को इस अभियान की सफलता की कुंजी माना गया।

साइबर अपराध को लेकर भी बैठक में गंभीर मंथन हुआ। डीजीपी ने स्वीकार किया कि साइबर अपराधी तकनीकी रूप से दक्ष, संसाधन सम्पन्न और कई बार महंगे कानूनी सलाहकारों से लैस होते हैं, ऐसे में पुलिस की तैयारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। रणनीति के तहत साइबर हेल्पलाइन, जिला स्तरीय रिस्पॉन्स सिस्टम और शिकायत से लेकर एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल तक की पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा पर जोर दिया गया। डिजिटल सबूतों की सुरक्षा, फॉरेंसिक मानकों का पालन और गवाहों की सुरक्षा को लेकर सख्त मानक तय करने की बात कही गई, ताकि अदालत में मामलों को मजबूती से पेश किया जा सके।

पारंपरिक अपराधों से आगे बढ़ते हुए बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी गहन चर्चा हुई। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आतंकवादी स्लीपर सेल की पहचान और उन्हें सक्रिय होने से पहले ही निष्क्रिय करना प्राथमिकता बताया गया। अधिकारियों को सतर्क किया गया कि स्थानीय शरारती तत्वों और सीमापार संगठित गिरोहों के गठजोड़ को किसी भी सूरत में पनपने न दिया जाए। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच संदिग्ध घुसपैठ और अवैध प्रवास पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए, जिसमें कानून और मानवाधिकारों के दायरे में रहकर निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। डीजीपी ओ.पी. सिंह ने पूरी रणनीति को केंद्र सरकार के 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था ही हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुलिस को खुद को केवल अपराध नियंत्रण एजेंसी नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का सुरक्षा सहयोगी मानकर काम करना होगा। निवेश, रोजगार और विकास का भरोसा तभी बनेगा, जब अपराधी खुद को हावी नहीं, बल्कि हर समय कानून के घेरे में महसूस करेंगे। अंत में डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस पूरी रणनीति की असली कसौटी थाना स्तर पर होगी। उन्होंने जिला पुलिस नेतृत्व से कहा कि एसएचओ की भूमिका नागरिक सुरक्षा की पहली दीवार है। स्थानीय इंटेलिजेंस को मजबूत करना, दोहराए जाने वाले अपराधियों पर नजर रखना, अपराध की हर तैयारी को समय रहते बाधित करना और जनता के बीच पुलिस की मौजूदगी को भरोसेमंद बनाना ही असली नेतृत्व की पहचान होगी। साइबर फ्रॉड से लेकर ड्रग नेटवर्क और आतंकी स्लीपर सेल तक, हरियाणा पुलिस तेज खुफिया जानकारी और सख्त कानून के सहारे उभरते अपराध से हमेशा तीन कदम आगे रहने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

छुट्टा पशुओं का कहर, कुसहरा से लेकर दो दर्जन गांवों तक किसानों की मेहनत रौंदी, खेती बचाने को रात-दिन पहरा

(जीएनएस)। गोरखपुर के जंगल कौड़िया क्षेत्र में बसे कुसहरा गांव और आसपास के लगभग दो दर्जन गांवों में इन दिनों किसानों की जिंदगी छुट्टा पशुओं के आतंक के साए में गुजर रही है। खेतों में लहलहाती फसलें अब उम्मीद नहीं, बल्कि चिंता का कारण बन चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में घूम रहे छुट्टा पशुओं के झुंड दिन-दहाड़े और खासकर रात के अंधेरे में खेतों में घुसकर गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मटर, दलहन और तिलहन जैसी रबी की फसलों को बेरहमी से रौंद रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कुसहरा समेत आसपास के गांवों में अब तक सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल जा रही है। राप्ती और रोहिन नदियों के बीच तलहटी क्षेत्र में बसे इन गांवों में खेती ही लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। लेकिन छुट्टा पशुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान बताते हैं कि पहले इक्का-दुक्का पशु खेतों में घुसते थे, जिन्हें किसी तरह भगाया जा सकता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब दर्जनों की संख्या में पशुओं के झुंड एक साथ खेतों में धावा बोलते हैं और जब तक किसान कुछ समझ पाएं, तब तक पूरी फसल चौपट हो जाती है। कई किसानों की तो आधी से ज्यादा जमीन की फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। कुसहरा गांव के किसान राम सिंह, विजय सिंह, शंभू गौड़, राकेश गुप्ता, संदलू कनौजिया और रामवृक्ष सदई निषाद बताते हैं कि रबी की फसल उन्होंने कर्ज लेकर

बोई थी। बीज, खाद, डीजल, सिंचाई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च किए गए थे। उम्मीद थी कि फसल तैयार होने पर अच्छी पैदावार मिलेगी, जिससे कर्ज उतरेगा और परिवार का खर्च चलेगा। लेकिन छुट्टा पशुओं ने उनकी सारी गणनाओं को बिगाड़ दिया। फसल कटने से पहले ही तबाह हो जाने से अब कर्ज चुकाने की चिंता उन्हें रातों की नींद नहीं लेने दे रही है।

रात के समय किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। ठंड और कोहरे के बावजूद किसान खेतों में अलाव जलाकर, टॉर्च और डंडे लेकर पहरा देने को मजबूर हैं। कई किसान पूरी-पूरी रात जागते हैं, फिर भी पशुओं के झुंड किसी न किसी तरफ से खेतों में घुस ही जाते हैं। एक किसान के खेत से पशु भगाने पर वे दूसरे किसान के खेत में घुस जाते हैं, जिससे गांव में आपसी तनाव की स्थिति भी बनने लगी है। कई परिवारों में बच्चे और महिलाएं भी निगरानी में जुटे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है और व्यक्तिगत स्तर पर फसलों की सुरक्षा करना लगभग असंभव हो गया है। सामूहिक प्रयास भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि छुट्टा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को डर है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में खेती करना घाटे का सौदा बन जाएगा और लोग खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। इससे न केवल किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।

किसानों का आरोप है कि छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। गौशालाएं या तो पर्याप्त संख्या में नहीं हैं या फिर वहां पहले से ही क्षमता से अधिक पशु रखे गए हैं। कई बार पकड़े गए पशु कुछ ही दिनों में फिर सड़कों और खेतों में नजर आने लगते हैं। इससे किसानों में यह भावना गहराती जा रही है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

किसानों की मांग है कि गांवों के आसपास स्थायी और पर्याप्त क्षमता वाली गौशालाओं की व्यवस्था की जाए, पहले से संचालित गौशालाओं में चारे, पानी और देखभाल की उचित व्यवस्था हो, ताकि वहां रखे गए पशु दोबारा सड़कों और खेतों में न छोड़े जाएं। साथ ही, नियमित रूप से अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की जाए। किसानों ने यह भी मांग की है कि अब तक हुई फसल क्षति का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे किसी तरह अगली फसल की तैयारी कर सकें और कर्ज के बोझ से थोड़ा उबर सकें।

इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी गौशालाएं बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है और प्रशासन समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है। हालांकि, किसानों का कहना है कि जब तक जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखेगी, तब तक उनकी परेशानी कम होने वाली नहीं है। जंगल कौड़िया क्षेत्र के कुसहरा और आसपास के गांवों में छुट्टा पशुओं का यह बढ़ता उत्पात अब केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो खेती से किसानों का भरोसा डगमगाने लगेगा और इसका असर दूरगामी होगा।

नि:शुल्क बारातशाला से गरीब परिवारों को मिला सम्मान और सहारा, सामाजिक आयोजनों का बोझ होगा हल्का

(जीएनएस)। कानपुर के हरबंस मोहाल क्षेत्र में रविवार को एक ऐसी पहल ने आकार लिया, जिसने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर राहत और उम्मीद की मुस्कान ला दी। आर्यनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विधायक निधि से निर्मित महर्षि वाल्मीकि बारातशाला का विधिवत लोकार्पण करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह, तिलक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन अक्सर भारी आर्थिक बोझ बन जाता है, ऐसे में यह निःशुल्क बारातशाला उनके लिए सम्मानपूर्वक आयोजन का मजबूत आधार बनेगी।

लोकार्पण समारोह के दौरान विधायक ने कहा कि सामाजिक आयोजनों में केवल रस्में ही नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान भी जुड़ा होता है। कई बार संसाधनों के अभाव में गरीब परिवार चाहकर भी अपने बच्चों के विवाह या अन्य पारिवारिक कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पाते, जिससे उन्हें सामाजिक दबाव और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि बारातशाला का निर्माण इसी सोच के साथ कराया गया है कि किसी भी परिवार को केवल पैसों की कमी के कारण अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों से समझौता न करना पड़े।

यह बारातशाला आम जनता के लिए

पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यहां विवाह, तिलक, जन्मदिन, सामाजिक बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बिना किसी शुल्क के किया जा सकेगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अब तक ऐसे आयोजनों के लिए निजी मैरिज हॉल या खुले मैदानों का सहारा लेना पड़ता था, जहां खर्च बहुत अधिक होता था। कई परिवार तो कर्ज लेकर या रिश्तेदारों से उधार लेकर कार्यक्रम करने को मजबूर होते थे। इस बारातशाला के बनने से न केवल उनका आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से करने का अवसर भी मिलेगा।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि हरबंस मोहाल और आसपास के इलाकों में लंबे समय से एक ऐसी सार्वजनिक सुविधा की मांग थी, जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बिना किसी परेशानी के सामाजिक आयोजन कर सकें। विधायक द्वारा इस मांग को पूरा किए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों ने इसे केवल एक भवन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और सहयोग का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि इस तरह की सुविधाएं समाज में आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करती हैं।

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि जब विकास कार्यों को केवल सड़कों और नालियों तक सीमित न रखकर सामाजिक जरूरतों से जोड़ते हैं, तो उसका सीधा लाभ आम जनता को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि बारातशाला आने वाले समय में क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के लिए सहारा बनेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो सीमित आय के बावजूद सामाजिक परंपराओं को निभाना चाहते हैं।

विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आगे भी इसी तरह के जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका मानना है कि विकास का असली अर्थ तभी है, जब उसका लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस बारातशाला का सदुपयोग करें और इसे सामूहिक संपत्ति की तरह संभालकर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में पार्षद रजत बाजपेयी, अंबर त्रिवेदी, कुतुबुद्दीन मंसूरी, पप्पन शर्मा, अमित बाल्मीकि उर्फ बिल्लू, चंकी गुप्ता, दीपा यादव, अनिल सोनकर, आकाश यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस पहल को गरीब और जरूरतमंदों के लिए बड़ी सौगात बताया। कुल मिलाकर, हरबंस मोहाल में बनी यह निःशुल्क बारातशाला न केवल एक भवन है, बल्कि सामाजिक समानता, सम्मान और सहयोग की भावना को मजबूती देने वाला कदम है, जो आने वाले वर्षों तक हजारों परिवारों के जीवन को आसान बनाएगा।

डिजिटल दुनिया में यूपी पुलिस की गूंज, सोशल मीडिया पर रचा इतिहास, विश्व स्तर पर छाया 'यूपी पुलिस मंथन'

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बार न सिर्फ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। सोशल मीडिया की दुनिया में यूपी पुलिस का नाम उस समय पूरी दुनिया में गूंज उठा, जब उसका हैशटैग लगातार दो घंटे से अधिक समय तक विश्व के टॉप ट्रेंड में बना रहा। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यह भी दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब पारंपरिक छवि से आगे बढ़कर आधुनिक, तकनीक-सक्षम और जनसंवाद को प्राथमिकता देने वाली संस्था के रूप में अपनी पहचान बना रही है। पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में 27 और 28 दिसंबर को आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन 'पुलिस मंथन' से जुड़ी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किया। इन पोस्टों में सम्मेलन की तस्वीरें, वीडियो, विचार-विमर्श के क्षण और भविष्य की रणनीतियों की झलक शामिल थी। देखते ही देखते यह कंटेंट आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। इसका असर यह हुआ कि 28 दिसंबर की शाम 5 बजकर 30 मिनट पर हैशटैग #यूपी_पुलिस_मंथन ट्रेंडिंग सूची में दर्ज हुआ और कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के ट्रेंड्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक स्थान पर पहुंच गया।

शाम 5 बजकर 45 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 45 मिनट तक यह हैशटैग लगातार विश्व के टॉप 5 ट्रेंड्स में बना रहा। इस

दौरान सोशल मीडिया यूजर्स की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। करीब 47 हजार से अधिक ट्वीट्स इस हैशटैग के साथ किए गए, जिससे इसकी पहुंच लगभग 3 करोड़ 86 लाख लोगों तक पहुंची। इतना ही नहीं, इस पर 2 लाख 46 हजार से अधिक बार इसे देखा गया और कुल मिलाकर 1.78 बिलियन से अधिक इंप्रेशन दर्ज किए गए। ये आंकड़े किसी भी सरकारी संस्था के लिए असाधारण माने जाते हैं और यह साबित करते हैं कि यूपी पुलिस की डिजिटल रणनीति कितनी प्रभावी रही।

यह पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस का कोई हैशटैग वैश्विक स्तर पर चर्चा में आया हो। इससे एक दिन पहले, 27 दिसंबर को भी #पुलिस_मंथन हैशटैग ने विश्व के टॉप ट्रेंड में जगह बनाई थी और दो घंटे से अधिक समय तक नंबर एक पर बना रहा। लगातार दो दिनों तक इस तरह की उपलब्धि हासिल करना यह दर्शाता है कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने सुनियोजित और रणनीतिक तरीके से जनसंपर्क को मजबूत किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी पुलिस की यह सफलता केवल सोशल मीडिया एक्टिविटी का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुलिसिंग में आए वास्तविक बदलाव, पारदर्शिता और जनविश्वास की भावना भी जुड़ी हुई है। जब किसी संस्था की जमीनी कार्यप्रणाली मजबूत होती है, तभी उसका प्रभाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देता है। पुलिस मंथन जैसे आयोजनों के जरिए जहां एक ओर वरिष्ठ अधिकारी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता तक इन प्रयासों की जानकारी पहुंचाने से भरोसा और संवाद दोनों मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया को केवल सूचना देने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि जनसंवाद और सहभागिता के मंच के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अपराध से जुड़ी सूचनाएं, ट्रैफिक एडवाइजरी, आपातकालीन संदेश, जनहित के वीडियो और सकारात्मक कार्यों की झलक सोशल मीडिया के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी का नतीजा है कि जब पुलिस मंथन से जुड़ा कंटेंट साझा किया गया, तो लोगों ने इसे केवल देखा ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में इसे साझा किया और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीं।

पुलिस मुख्यालय की ओर से यह भी बताया गया कि इस ट्रेंड में शामिल होने वाले ट्वीट्स में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आईं। प्रवासी भारतीयों, सुरक्षा विशेषज्ञों और आम नागरिकों ने यूपी पुलिस के प्रयासों की सराहना की। कई लोगों ने इसे आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया, तो कई ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक माना। डिजिटल युग में किसी भी सरकारी संस्था के लिए सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यूपी पुलिस ने यह साबित कर दिया कि यदि कार्य ईमानदारी से किए जाएं और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो जनता स्वतः जुड़ती है। 'यूपी पुलिस मंथन' का वैश्विक ट्रेंड बनना इसी का उदाहरण है। यह केवल एक हैशटैग की सफलता नहीं, बल्कि उस विश्वास की अभिव्यक्ति है, जो धीरे-धीरे पुलिस और जनता के बीच मजबूत हो रहा है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस उपलब्धि के जरिए यह संदेश दिया है कि वह न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है, बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली संस्था भी है। सोशल मीडिया पर विश्व स्तर पर छाया यह हैशटैग आने वाले समय में अन्य सरकारी विभागों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है, कि कैसे तकनीक और जनसंपर्क के सही इस्तेमाल से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है।

बेटियों के नाचने पर भड़का पिता, जन्मदिन की खुशियां बनीं खूनी मातम, साले की चाकू मारकर हत्या

(जीएनएस)। मेरठ। गुलमर्ग कॉलोनी में रविवार देर रात एक जन्मदिन समारोह उस समय खौफनाक वारदात में बदल गया, जब परिवार की खुशियों, संगीत और हंसी के बीच पनपा गुस्सा खून-खराबे का कारण बन गया। बेटियों के डांस को लेकर नाराज एक व्यक्ति ने आपा खोते हुए अपने ही साले की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आए भांजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुछ ही घंटों में घर का जश्न मातम में बदल गया और पूरा मोहल्ला सन्न रह गया।

घटना की शुरुआत गुर्जर चौक कॉलोनी निवासी चांद की बेटी गुलफ्शा के जन्मदिन से हुई थी। रविवार को घर में जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी, जिसमें परिवार के लोग और रिश्तेदार जुटे थे। घर में सजावट थी, केक काटने की तैयारी थी और बच्चे-बड़े सभी खुशी के माहौल में गाने-बजाने और नाचने में लगे थे। इसी पार्टी में चांद का साढ़ू सलीम भी अपनी पत्नी नरगिस और दो बेटियों के साथ शामिल हुआ था। सलीम का साला यूनुस भी अपने बच्चों के साथ वहां मौजूद था।

पार्टी के दौरान जब लड़कियां डांस कर रही थीं, तभी सलीम को इस पर आपत्ति हो गई। उसने नाराजगी जताई और माहौल से खफा होकर अपनी बेटियों को लेकर पार्टी बीच में ही छोड़ दी और गुलमर्ग कॉलोनी स्थित अपने

घर चला गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नाराजगी इतनी भयावह शक्ल ले लेगी। रात करीब साढ़े दस बजे जब उसकी पत्नी नरगिस घर पहुंची, तो सलीम का गुस्सा और भड़क उठा। बताया गया कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

पति की मारपीट से परेशान नरगिस ने फोन कर अपने भाई यूनुस को सारी बात बताई और मदद की गुहार लगाई। बहन की हालत सुनकर यूनुस अपने बेटे नौशाद के साथ तुरंत सलीम के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। बात बढ़ती चली गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान सलीम ने गुस्से में घर में रखा चाकू उठा लिया और यूनुस के सीने पर एक के बाद एक कई वार कर दिए।

जब यूनुस लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसका भांजा नौशाद अपने मामा को बचाने के लिए आगे आया, तो आरोपी ने उसकी पीठ में भी चाकू घोंप दिया। अचानक हुए इस हमले से घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर दौड़े। गंभीर हालत में घायल यूनुस और नौशाद को आनन-फानन में प्यारेलाल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान यूनुस ने दम तोड़ दिया। नौशाद की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की जड़ पारिवारिक सोच और बेटियों के डांस को लेकर उपजा गुस्सा था, जो धीरे-धीरे हिंसा में बदल गया।

यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी बन गई, बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर गई है। जिस घर में कुछ घंटे पहले बच्चों की हंसी और जन्मदिन की खुशियां गूंज रही थीं, वहां अब मातम पसरा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग, योगी सरकार के सुधारों से निवेश का नया भरोसा

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने देश-विदेश के निवेशकों का ध्यान एक बार फिर प्रदेश की ओर खींचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते कुछ वर्षों में किए गए प्रशासनिक, नीतिगत और तकनीकी सुधारों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कभी जटिल प्रक्रियाओं, लंबित अनुमतियों और निवेशकों की शिकायतों के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उद्योगों और उद्यमियों के लिए भरोसेमंद और निवेशक-अनुकूल राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

योगी सरकार ने 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के सिद्धांत को जमीन पर उतारते हुए व्यापार और उद्योग से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, फाइलों की देरी और अलग-अलग विभागों की जटिल शर्तों को खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर डिजिटल सिस्टम को अपनाया गया। सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को एक ही मंच पर सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल तेजी से सुधरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश की यात्रा इस बदलाव की कहानी खुद बयान करती है। वर्ष 2017-18 में जहां उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, वहीं 2019 में उसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद 2022 और 2024 में प्रदेश को टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया। यही नहीं, लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भी 2022, 2023 और 2024 में उत्तर प्रदेश को अचीवर का दर्जा मिला, जबकि 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में वाणिज्य एवं उद्योग श्रेणी में प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा। ये आंकड़े इस

बात के गवाह हैं कि सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जमीन पर उनका असर दिखा है।

बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश को उद्यम स्थापना, श्रम कानूनों के सरलीकरण और भूमि प्रशासन जैसे तीन अहम क्षेत्रों में टॉप अचीवर घोषित किया गया। यह उपलब्धि सरकार की उस नीति को दर्शाती है, जिसमें उद्योगों के सामने आने वाली बाधाओं को पहचानकर उन्हें दूर करने पर लगातार काम किया गया। वर्ष 2024 के बाद BRAP और BRAP+ के अंतर्गत प्रदेश में 24 सुधार क्षेत्रों में कुल 426 महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। इन सुधारों में उद्यम पंजीकरण, निवेश सुविधा, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति, निर्माण अनुमति और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाया गया है।

योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' को माना जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की जा चुकी हैं और 97 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया गया है। सभी लाइसेंस और अनुमतियों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने से भौतिक फाइलिंग पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगा है। निवेश मित्र पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि 96 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता इसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। यह संतुष्टि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में बढ़ते निवेश प्रस्तावों, नई औद्योगिक इकाइयों और रोजगार के अवसरों के रूप में भी दिखाई दे रही है। सरकार का मानना है कि निवेशकों का भरोसा तभी बनता है, जब नीतियां स्पष्ट हों, प्रक्रियाएं सरल हों और निर्णय समय पर लिए जाएं, और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अब प्रदेश सरकार निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है, जिसे राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह नया संस्करण IGRS, निवेश सारथी, OIMS, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और मुख्यमंत्री दर्पण जैसी प्रमुख प्रणालियों से एकीकृत होगा। निवेश मित्र 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट डैशबोर्ड, रियल-टाइम डेटा एनालिसिस, उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली और व्हाट्सएप, ईमेल व एसएमएस के जरिए सूचनाओं की सुविधा दी जाएगी। इससे निवेशकों और सरकार के बीच संवाद और प्रक्रियाएं और अधिक सहज, तेज और प्रभावी होंगी।

कुल मिलाकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की यह बड़ी छलांग केवल एक रैंकिंग की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक है, जो योगी सरकार के सुधारों के चलते निवेशकों और उद्योग जगत में बना है। बदले हुए प्रशासनिक माहौल, मजबूत नीतियों और डिजिटल शासन के सहारे उत्तर प्रदेश अब देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में अपनी जगह मजबूती से स्थापित कर चुका है।

बीजेपी के भीतर जातीय बैठकों से बढ़ा सियासी तापमान, संगठन में शक्ति संतुलन की जंग खुलकर आई सामने

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा में इन दिनों अंदरूनी सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पहले ठाकुर विधायकों की बैठक, फिर कुर्मी नेताओं की जुटान और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने पार्टी के भीतर चल रहे 'पावर शो' को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया है। हालात ऐसे बन गए कि प्रदेश अध्यक्ष को खुद सामने आकर चेतावनी जारी करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद संगठन के भीतर जाति और क्षेत्र के नाम पर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। यही कारण है कि न केवल भाजपा के अंदर, बल्कि विपक्ष में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के भीतर यह चर्चा उस वक्त शुरू हुई, जब विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की अगुआई में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद कल्याण सिंह और अवंतीबाई लोधी के नाम पर लोध नेताओं की जुटान देखने को मिली। फिर जन्मदिन समारोह के बहाने कुर्मी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसने संगठन के भीतर संदेश दे दिया कि अलग-अलग जातीय समूह अपनी ताकत दिखाने के मूड में हैं। हाल ही में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान कुशीनगर विधायक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक और भोज ने इस पूरे घटनाक्रम को और हवा दे दी।

इन बैठकों ने विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी के नेता इसे भाजपा के भीतर गहराते असंतोष और आपसी खींचतान का प्रमाण

बता रहे हैं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मणों को खुले तौर पर अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया और कहा कि समाजवाद में सभी वर्गों को सम्मान मिलता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के अंदर मचे इस घमासान को लेकर दावा किया कि असल वजह जातीय बैठकें नहीं, बल्कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद सामने आए आंकड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नाम कटने की बात सामने आई है। अखिलेश के इस बयान पर भाजपा के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सपा पर पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी संगठन के भीतर हलचल थमी नहीं। पश्चिम क्षेत्र में उनके स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष और कई बड़े नेता नजर नहीं आए, जिसने अंदरूनी असंतोष की अटकलों को और बल दे दिया। इसी बीच, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी द्वारा अपने आवास पर धोबी समाज की बैठक आयोजित किए जाने से यह संदेश गया कि चेतावनियों के बावजूद अलग-अलग सामाजिक समूह अपनी मौजूदगी और ताकत दर्ज कराने से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

दरअसल, भाजपा के भीतर यह पूरा घटनाक्रम संगठन और सत्ता में अपनी जगह सुरक्षित करने की कवायद से जुड़ा माना जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और अब प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं भी लंबे समय से चल रही हैं। माना जा रहा है कि कुछ संगठनात्मक चेहरे सरकार में जा सकते हैं और कुछ मंत्री संगठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में नेता अभी से अपनी राजनीतिक हैसियत और समर्थन दिखाकर भविष्य की सूची में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं।

आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव भी इस घमासान की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपेक्षा से कम सफलता मिली थी और यह आकलन सामने आया कि विपक्ष के पीडीए फार्मूले के कारण ओबीसी, खासकर कुर्मी वोटरों में सेंध लगी। इसी के बाद से भाजपा संगठन में ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिशें तेज हुईं। इसका असर यह हुआ कि सवर्ण वर्ग के भीतर यह भावना पनपने लगी कि उनकी भूमिका और अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी असंतुलन ने सवर्ण नेताओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए संगठित बैठकों की ओर प्रेरित किया।

दूसरी ओर, विपक्ष इस स्थिति को अवसर के रूप में देख रहा है। बिहार के हालिया चुनावी अनुभव को सामने रखते हुए विपक्षी दल सवर्णों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा के भीतर चल रहा यह शक्ति संघर्ष उन्हें अपने पक्ष में माहौल बनाने का मौका देता दिख रहा है। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि वह अब तक सवर्णों को अपना कोर वोटर मानती रही है, लेकिन यदि इस वर्ग में असंतोष गहराया तो इसका असर आगामी चुनावों में पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, भाजपा के भीतर चल रही जातीय बैठकों और 'पावर शो' ने यह साफ कर दिया है कि संगठन के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है। यह सिर्फ बैठकों या भोज तक सीमित मामला नहीं, बल्कि 2027 की तैयारी, संगठन और सरकार में हिस्सेदारी तथा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा एक गहरा सियासी संघर्ष है, जिसका असर आने वाले महीनों में और साफ दिखाई दे सकता है।

साधु-संतों के सम्मान पर अहंकार भारी, भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार

(जीएनएस)। लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर और तीखा हमला करते हुए कहा है कि सत्ता का अहंकार किसी भी कीमत पर सच्चे साधु-संतों के मान-सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में धर्म और आस्था की सदियों पुरानी परंपराओं का खुलेआम अपमान हो रहा है और साधु-संतों को अपने धार्मिक और जनकल्याणकारी कार्यों के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने तक की नौबत आ गई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ और माघ मेले जैसी विशाल धार्मिक परंपराएं भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक रही हैं, जहां हमेशा से प्रशासन स्वयं साधु-संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता रहा है और उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करता रहा है। लेकिन भाजपा शासन में हालात इतने बदल गए हैं कि धर्म के कार्य के लिए अस्थायी भूमि तक के आवंटन के लिए संत समाज को अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जमीनों पर स्थायी कब्जा जमाए बैठे हैं, वही लोग धर्मार्थ कार्यों के लिए दूसरों को जमीन देने में आनाकानी कर रहे हैं, जो भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का घोर अपमान है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यक्तिगत दंभ और सत्ता का अभिमान है, जो एक दिन अवश्य हारता है। उन्होंने

सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर अधिकारी संत समाज के साथ इस तरह का व्यवहार करने का दुस्साहस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी समझदार और संवेदनशील अधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे समाज में आक्रोश फैले। सब जानते हैं कि अधिकारी किसके दबाव और भय में काम करते हैं और किसके आदेश पर उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं।

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने को सबसे ऊपर दिखाने के लिए समाज के अन्य वर्गों, यहां तक कि साधु-संतों को भी नीचा दिखाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इतिहास गवाह है कि अधर्म कभी नहीं जीतता और एकाधिकार की भावना अंततः पराजित होती है। सत्ता का अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह समाज की आस्था और विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता।

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में उत्तर प्रदेश में हर तरह का अपराध और अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नशे का कारोबार ऊपर से नीचे तक फैल चुका है और ऐसा लगता है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। अपराधी और माफिया बेखौफ होकर नशीले और जहरीले कारोबार चला रहे हैं और उन्हें सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं और बढ़ते अपराधों पर आंखें मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न युवा और न ही व्यापारी। आम जनता असुरक्षा और भय के माहौल में जीने को मजबूर है, जबकि सरकार केवल प्रचार और दावे करने में व्यस्त है।

अंत में सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता सब देख और समझ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में जनता भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर प्रदेश को अपराध, नशे और अहंकार से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के सम्मान, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी और सत्ता के दंभ के आगे कभी नहीं झुकेगी।

बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी में मिलेगी बड़ी राहत, ईंधन अधिभार में कटौती से बिलों में 2 .33 प्रतिशत की कमी, राज्य विद्युत परिषद का बड़ा फैसला

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी 2026 के महीने में अपने बिजली बिलों में 2.33 प्रतिशत की कटौती का लाभ मिलेगा। पावर कॉरपोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अक्टूबर 2025 के ईंधन अधिभार का समायोजन अगले महीने किया जाएगा। इस कदम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

पिछले साल सितंबर का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर लगभग 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान में बिजली कंपनियों के पास कुल 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस जमा है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि लगभग 18,592 करोड़ रुपये और बढ़ने की संभावना है, जिससे कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।

वर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक यह विशाल राशि बिजली कंपनियों के पास उपलब्ध है, तब तक उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूल करना उचित नहीं

है। केवल तब ही अधिभार वसूला जा सकता है, जब यह सरप्लस समाप्त हो या कमी की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ पहले ही लागू किया जा चुका है और नई बिजली दरें प्रभावी हो चुकी हैं। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और भुगतान प्रक्रियाओं में आसान पहुंच सुनिश्चित हुई है।

प्रदेश सरकार की इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि बिजली खपत पर भी नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल माध्यम से जारी की जा चुकी हैं और 97 प्रतिशत से अधिक आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है और भौतिक फाइलिंग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में कमी जारी रहने की संभावना है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं की जेब पर असर कम होगा और उन्हें बिजली के इस्तेमाल में राहत का अनुभव होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम प्रदेश में बिजली की आपूर्ति और उपभोग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 2.33 प्रतिशत कम बिल का लाभ मिलने से न केवल घरेलू परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि छोटे और बड़े व्यवसायों को भी अपनी बिजली लागत कम करने में मदद मिलेगी। इससे आर्थिक दबाव घटेगा और प्रदेश में व्यापार और उद्योगिक गतिविधियों के लिए भी अनुकूल माहौल बनेगा। साथ ही यह कदम सरकार की यह प्रतिबद्धता भी दर्शाता है कि बिजली उपभोक्ताओं के हित में समय-समय पर आवश्यक फैसले लिए जाते रहेंगे।

यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार देकर एक बहुत लंबी अख़बार की स्टोरी के रूप में 900–1000 शब्दों में तैयार कर दूँ, जिसमें बिजली बिलों की कटौती, सरप्लस राशि का विश्लेषण, डिजिटल सेवाओं का लाभ और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हों। क्या मैं ऐसा कर दूँ?

जनता को भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगामी चुनाव में बढ़त का जताया विश्वास

(जीएनएस)। फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की प्रमुख बेबी रानी मौर्य ने रविवार को साफ संदेश दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछली बार की अपेक्षा और अधिक सीटें जीतकर दोबारा राज्य में सत्ता में आएगी। मंत्री मौर्य ने यह बात फिरोजाबाद में आयोजित व्यापारी सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करती है और यही भाजपा की ताकत का स्रोत है। बेबी रानी मौर्य ने कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है और सरकार की कार्यप्रणाली, नीति और विकास कार्य जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता स्पष्ट रूप से देख

रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि लोग भाजपा पर भरोसा रखते हैं और आगामी चुनाव में इसे प्रकट करेंगे। मंत्री ने व्यापारी सम्मेलन में भी व्यापारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले और उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और सभी वर्गों के लोगों का सम्मान किया जाता है, जिससे सामाजिक समरसता और व्यापारिक समुदाय में आपसी विश्वास बढ़ता है। मौलिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मथुरा में मुस्लिम समाज की पंचायत के फैसले और मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के विवाद पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में कानून का राज है और कोई भी निर्णय कानूनी दायरे के बाहर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में राम जी का नाम जोड़ने के कदम पर राजनीति करना उचित नहीं है और यह केवल विकास और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। व्यापारी सम्मेलन के दौरान बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश के विकास और निवेश को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छोटे और बड़े व्यापारियों के हित में कई उपाय किए हैं, जिससे व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन सेवाएं और व्यापारिक लाइसेंस की सरल प्रक्रियाएं व्यापारियों को राहत दे रही हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापार और उद्योग को आसान बनाने के लिए नीति और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल लगातार मजबूत हो रहा है।

साल के आखिरी 'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के समग्र विकास और काशी तमिल संगमम पर किया जोर

(जीएनएस)। वाराणसी। वर्ष 2025 के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 129वां संस्करण सुनने के लिए वाराणसी में व्यापक उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में न केवल देशवासियों से संवाद किया, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने बूथों और कार्यालयों पर एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के संदेशों को सुने और उनके बताए मार्गदर्शन को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

वाराणसी महानगर के विभिन्न बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सुनकर सक्रिय भागीदारी दिखाई। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कैंट विधानसभा के रविदास मंडल स्थित बूथ संख्या 133 में कार्यक्रम का आनंद लिया। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कंचनपुर वार्ड के बूथ संख्या 185 पर और क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी तथा संतोष सोलापुरकर ने अपने-अपने बूथों पर सामूहिक रूप से 'मन की बात' को सुना। प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने सिगरा क्षेत्र के राजन शाही कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम का पालन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि देशवासियों के मन को जोड़ने और दिशा देने वाला सशक्त मंच है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने तुलसी उद्यान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना और प्रधानमंत्री के वाराणसी से जुड़े विशेष दृष्टिकोण पर जोर दिया। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि काशी में अधोसंरचना, सड़क और घाट विकास, मंदिर क्षेत्र का कायाकल्प, स्वच्छता, पर्यटन, विद्युत व्यवस्था, आवागमन और नागरिक सुविधाओं में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व के परिणामस्वरूप काशी न केवल आध्यात्मिक राजधानी के रूप में बल्कि आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में भी देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रही है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर काशी में आयोजित चौथे काशी तमिल संगमम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संगमम में तमिल भाषा सीखने पर जोर दिया गया और काशी के 50 से अधिक स्कूलों में इस दिशा में विशेष अभियान चलाए गए। बच्चों और युवाओं में तमिल भाषा को लेकर नया आकर्षण देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे भाषा की ताकत और भारत की एकता का प्रतीक बताया।

कार्यक्रम में कैंट भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' के जरिए प्रधानमंत्री जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करते हैं और समाज के हर वर्ग तक प्रेरक संदेश पहुंचाते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेशों को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि अपने जीवन और समाज में उन्हें लागू करने का प्रयास करें।

कुल मिलाकर, वर्ष 2025 के अंतिम 'मन की बात' कार्यक्रम ने न केवल वाराणसी के समग्र विकास पर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि काशी तमिल संगमम जैसी सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से भाषा और संस्कृति के महत्व को भी उजागर किया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व ने काशी को आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों दृष्टियों से देश और दुनिया में विशेष स्थान दिलाया है।